"उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)}(संशोधन) विधेयक, 2021" (उत्तराखण्ड विधेयक संख्यावर्ष, 2021)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण), अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में संशोधन करने हेतु:—

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- धारा 3 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 में—
 - (i) उपधारा (8) के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात्—
 - ''(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष और,
 - (ख) उपाध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"
 - (ii) उपधारा (8) के पश्चात् नई उपधारा (8क) निम्नवत अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
 - ''(8क). उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोकसेवा (अधिकरण)} (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का पद धारण करने वालों पर भी लागू होंगे।''

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)}(संशोधन)
विधेयक, 2021, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथा
उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में संशोधन किये जाने विषयक है।

2— प्रस्तावित विधेयक द्वारा किसी प्रकार की विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

> पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का संशोधन मात्र है।

- प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
- 2. विधेयक के खण्ड 2 में धारा 3 में संशोधन की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक **उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा** (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 की धारा 3 की उपधारा 8 में संशोधन किये जाने विषयक है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति को कोई भी व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

> पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

By the Tribunal Reforms Act, 2021, the Central Government has fixed the maximum age of Chairpersons of the Tribunals constituted under the Central Acts as seventy (70) years and members as sixty-seven (67) years. Functions of Uttarakhand Public Services Tribunal are similar to State Administrative Tribunals, which are established under the Administrative Tribunals Act, 1985 (Act no. 13 of 1985), which decide service-related disputes of officers and employees of the states. This Tribunal is established under the UP Public Services (Tribunal) 1976 (as applicable to the state of Uttarakhand) and decides service-related disputes of public servants of the State of Uttarakhand.

- 2- Therefore, after due consideration, a Bill is presented to amend the U.P. Public Services (Tribunal) Act, 1976, in its application to the State of Uttarakhand, to bring the same in conformity with the central enactments, by increasing the maximum age for holding the office of the Chairman of the Tribunal from sixty-seven (67) years to seventy (70) years and of the other members, from sixty-five (65) years to sixty-seven (67) years.
- 3- Proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

THE UTTARAKHAND {(UTTAR PRADESH) PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL)} (AMENDMENT) BILL, 2021 (UTTARAKHAND BILL NO. of 2021)

A

BILL

further to amend the {(Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal) } Act, 1976, (as applicable in the State of Uttarakhand) in the context of Uttarakhand State.

Be it enacted by Legislative Assembly of Uttarakhand in the seventy-second year of the Republic of India as follows:

Short title and 1. commencement

- (1) This Act may be called the Uttarakhand {(Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal)} (Amendment) Act, 2021.
- (2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

- 2. In the {(Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal)} Act, 1976, (as applicable in the State of Uttarakhand) in section 3—
 - (i) For clause (a) and (b) of sub-section (8) the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) In case of Chairman, the age of seventy years, and
 - (b) In case of Vice-chairman and any other member, the age of sixty seven years."
 - (ii) After sub-section (8) the following new sub-section (8A) shall be inserted, namely-

"(8-A) The provisions of sub-section (8), as amended by the Uttarakhand {(Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal)} (Amendment) Act, 2021, shall also apply to the Chairman, Vice-Chairman, and other members holding office on the Commencement of the said Act."

Memorandum Regarding Clause-wise of the Bill

The proposed Bill is only an amendment to the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) Act, 1976 (as applicable to the State of Uttarakhand).

- 1. In clause 1 of proposed Bill, it is to be proposed to provide for the arrangement of short title, extent and commencement.
- 2. In clause 2 of the Bill, provision for amendment of section 3 is to be proposed.

Memorandum Regarding Delegated Legislation

The proposed Uttarakhand {(Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal)} (Amendment) Bill, 2021, the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) Act, 1976 (as applicable in the State of Uttarakhand) is subject to the amendment.

2- Delegation of legislative power is not proposed in the proposed Bill.

Financial Memorandum

The proposed Bill is subject to amendment in sub-section (8) of section 3 of the Uttarakhand {(Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal)} (Amendment) Bill, 2021.

2- The proposed Bill does not involve any expenditure of recurring and non-recurring nature from Consolidated Fund of the state.